भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय
....
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-3204
जिसका उत्तर 04 अगस्त, 2022 को दिया जाना है ।

इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहन

3204. श्री महाबली सिंहः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार देश में इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को प्रोत्साहन देने के लिए कोई योजना तैयार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पूरे देश में चार्जिंग स्टेशनों की संख्या बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या सरकार ने चार्जिंग स्टेशनों पर ही बैटरी बदलने की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कोई नीति बनाई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री
(श्री आर.के. सिंह)

(क) और (ख) : सरकार ने देश में इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

(i) भारी उद्योग मंत्रालय (एमएचआई) ने इलेक्ट्रिक वाहनों के अभिग्रहण को प्रोत्साहित करने के लिए वर्ष 2015 में भारत में (हाइब्रिड एवं) विद्युत वाहनों के त्वरित अधिग्रहण और विनिर्माण (फेम इंडिया) स्कीम तैयार की। इस समय फेम इंडिया स्कीम के चरण-II का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

(ii) सरकार ने एडवांस्ड कैमिस्ट्री सैल बैट्री के निर्माण के लिए उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन स्कीम अनुमोदित की है।

(iii) इलेक्ट्रिक वाहनों को ऑटोमोबाइल तथा ऑटो संघटकों के लिए उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन स्कीम के तहत कवर किया गया है।

(iv) इलेक्ट्रिक वाहनों पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% की गई है। चार्जरों/चार्जिंग स्टेशनों पर जीएसटी 18% से घटाकर 5% की गई है।

(v) सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने बैटरी चालित परिवहन वाहनों को परमिट की आवश्यकता से छूट दी है।

(vi) सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रयोग को बढ़ावा देने और सहभागी मोबिलिटी के साथ-साथ सार्वजनिक परिवहन में शून्य उत्सर्जन वाले वाहनों की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए दिनांक 17.07.2019 को राज्यों के लिए एडवाइजरी जारी की है।

(ग) : पूरे देश में चार्जिंग स्टेशनों की संख्या में वृद्धि करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

(i) विद्युत मंत्रालय ने एक स्पष्टीकरण जारी किया है कि चार्जिंग स्टेशन के माध्यम से इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरी चार्ज करने के लिए किसी प्रकार के लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है।

(ii) केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) ने चार्जिंग स्टेशनों के लिए ग्रिड कनेक्टिविटी और विद्युत आपूर्ति की सुरक्षा के लिए तकनीकी मानक संबंधी विनियमों में संशोधन जारी किए हैं।

(iii) देश में ई-मोबिलिटी पारगमन में तेजी लाने के लिए विद्युत मंत्रालय द्वारा दिनांक 14.01.2022 को समेकित संशोधित दिशानिर्देश और चार्जिंग अवसंरचना के लिए मानदंड जारी किए गए हैं।

(iv) ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) का चयन इलेक्ट्रिक वाहनों की चार्जिंग अवसंरचना के संवर्धन के लिए विभिन्न पहलें करने हेतु केंद्रीय नोडल एजेंसी के रूप में किया गया है।

(v) सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारी उद्योग मंत्रालय और नीति आयोग सहित विद्युत मंत्रालय ने इलेक्ट्रिक वाहनों के फायदों के बारे में आम जनता को जानकारी देने के लिए दिनांक 19.02.2021 को एक राष्ट्रव्यापी "गो इलेक्ट्रिक" अभियान शुरू किया है।

(vi) ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) द्वारा सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों की संस्थापना के लिए 9 प्रमुख शहरों के लिए कार्य योजना तैयार की गई है। प्रारंभिक अनुमानों के अनुसार, इन शहरों में वर्ष 2030 तक कुल 46,397 सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन (पीसीएस) स्थापित करने का लक्ष्य है।

(vii) सभी केंद्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे परिवर्तनशील गतिशीलता संबंधी भारत सरकार की पहल में शामिल हों और अपने आधिकारिक वाहनों के बेड़े को वर्तमान पेट्रोल/डीजल वाहनों से इलेक्ट्रिक वाहनों में परिवर्तित करें।

(viii) फेम-I के अंतर्गत संस्वीकृत 520 चार्जिंग स्टेशनों के साथ-साथ सरकार ने देश के 68 शहरों में 2877 सार्वजनिक ईवी चार्जिंग स्टेशन और 9 प्रमुख एक्सप्रेसवे तथा 16 राजमार्गों पर 1876 सार्वजनिक ईवी चार्जिंग स्टेशन संस्थापित करने की संस्वीकृति प्रदान की है।

(ix) आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग अवसंरचना के संबंध में मॉडल बिल्डिंग उप-नियम तथा शहरी और क्षेत्रीय विकास योजनाओं, निर्माण और कार्यान्वयन दिशानिर्देशों में संशोधन जारी किए हैं।

(घ) और (ङ) : वर्ष 2022-23 के बजट भाषण के दौरान, यह घोषणा की गई है कि बड़े पैमाने पर चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए शहरी क्षेत्रों में स्थान संबंधी बाधाओं पर विचार करते हुए, एक बैटरी स्वैपिंग नीति लाई जाएगी और अंतर-प्रचालकता मानक तैयार किए जाएंगे। निजी क्षेत्र को 'सेवा के रूप में बैटरी अथवा ऊर्जा' के लिए स्थिर एवं नवीन व्यापार मॉडल विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इससे ईवी परितंत्र दक्षता में सुधार होगा।

****